वर्ष 1 · अंक 08
जयपुर, रविवार, 27 सितम्बर 2026
सप्ताह 21–27 सितम्बर 2026

The Consulting Crew
GST · इनकम टैक्स · ROC · पेरोल · सलाह
क्लाइंट्स और दोस्तों के लिए मुफ़्त

THE CONSULTING CREW

आज के समाचार

BUSINESS WEEKLY

हर खबर जो आपके बिज़नेस के काम आए

रेपो रेट	टैक्स ऑडिट	निफ्टी 50	सेंसेक्स	NSE लिस्टिंग	GST काउंसिल
5.25%	30 Sep	23,140.50	73,895.74	+0.84%	7 Oct
MPC 7 अक्टूबर	▼ extension नहीं	▼ -0.9%, सातवाँ घाटे का हफ़्ता	▼ हफ़्ते में -0.5%	₹22,562 करोड़, 5.71 गुना	तरीक़े, दरें नहीं

इस अंक में

1 टैक्स · 2 टैक्स डेस्क · 3 GST डेस्क · 4 क्रेडिट डेस्क · 5 मार्केट डेस्क · 6 ट्रेड डेस्क · 7 राजस्थान डेस्क · 8 रेफ़रेंस · + ज़रूरी तारीख़ें

बड़ी खबर · टैक्स

extension नहीं आया। ऑडिट रिपोर्ट बुधवार को देनी है

जिस-जिस संस्था ने माँगा, जवाब चुप्पी रहा — और टैक्स के मामले में चुप्पी भी जवाब है। क़ानून में जो तारीख़ है, वही तारीख़ है।

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट AY 2026-27 · s.44AB · 30 सितम्बर 2026

पिछले हफ़्ते इस अख़बार ने कहा था कि माँगे गए मगर मिले नहीं extension के भरोसे योजना मत बनाइए। वही सही तरीक़ा था। **25 सितम्बर** तक CBDT ने कुछ अधिसूचित नहीं किया, और section 44AB की रिपोर्ट **30 सितम्बर 2026** को ही देनी है — बुधवार, इस अंक की तारीख़ के तीन दिन बाद। पेशेवर संस्थाओं ने 31 अक्तूबर माँगा; मना नहीं किया गया, जवाब ही नहीं आया — और टैक्स के मामले में दोनों एक ही बात है।

यह साफ़ समझ लेना ठीक रहेगा कि extension क्यों नहीं आया, क्योंकि यही तर्क अगले साल भी चलेगा। extension हमेशा तब आए हैं जब portal बैठ गया हो या कोई आपदा काम रोक दे — वे किसी चीज़ के टूटने का जवाब होते हैं। इस सितम्बर कुछ टूटा नहीं। और सरकार की जेब ने भी तर्क का साथ नहीं दिया: 17 सितम्बर तक net direct tax **₹12.12 लाख करोड़**, **12.96%** ऊपर, advance tax **16.18%** ऊपर। जो विभाग अपने आँकड़ों से आगे चल रहा हो उसे वक़्त ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, और संस्थाएँ काम के बोझ से राहत माँग रही थीं, किसी नाकामी से नहीं। सितम्बर में पेशे के लिए यह सच्ची दिक़्क़त है। extension का आधार यह कभी नहीं रहा।

> **आपको क्या करना है**
>
> सोमवार सुबह दो बात कर लीजिए, बुधवार दोपहर नहीं। auditor से पूछिए कि वे किस तारीख़ को sign करेंगे — तारीख़, इरादा नहीं — और वह 30 सितम्बर के बाद पड़े तो अभी तय कीजिए कि दबाव बनाना है या जुर्माना जानकर मान लेना है। और यह भी देख लीजिए कि रिपोर्ट और return में घालमेल न हो: रिपोर्ट 30 सितम्बर को, और ऑडिट वालों की return 31 अक्तूबर को। रिपोर्ट देर से जाने पर return की तारीख़ नहीं खिसकती; बस return ऐसी जाती है जिसका ऑडिट देर से भरा गया, और दोनों बातें एक ही record पर बैठी रहती हैं।

ज़रूरी तारीख़ें

सितम्बर – नवंबर 2026

30 सित — आज ही
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट
Form 3CA/3CB और 3CD

7 अक्टू — 7 दिन बाकी
TDS जमा
सितंबर का — और उसी दिन GST काउंसिल तथा MPC, दोनों बोलेंगे

11 अक्टू — 11 दिन बाकी
GSTR-1
सितंबर का

15 अक्टू — 15 दिन बाकी
TCS रिटर्न — Q2
Form 27EQ

18 अक्टू — 18 दिन बाकी
CMP-08 — Q2
कंपोज़िशन वाले

20 अक्टू — 20 दिन बाकी
GSTR-3B
सितंबर का, मासिक वाले

31 अक्टू — 31 दिन बाकी
ITR — ऑडिट वाले
साथ में MSME-1 (छमाही)

15 नव — 46 दिन बाकी
TDS सर्टिफ़िकेट — Q2
Form 16A

30 नव — 61 दिन बाकी
ITR — ट्रांसफर प्राइसिंग
s.92E वाले

ये आम तारीख़ें हैं। सरकार आगे बढ़ाए तो अगले अंक में बता देंगे। टर्नओवर और राज्य के हिसाब से फ़र्क़ पड़ता है — भरोसा करने से पहले एक बार पूछ लीजिए।

सारी तारीख़ें कैलेंडर में डालें

टैक्स डेस्क · जुर्माना

देर से गई ऑडिट रिपोर्ट की असली क़ीमत, और जो एक चीज़ उसे घटाती है

s.271B · turnover का 0.5% या ₹1,50,000, जो कम हो · s.273B

Section 271B का जुर्माना है **turnover का 0.5% या ₹1,50,000, जो कम हो**। इसे पढ़ने वाले ज़्यादातर कारोबारों पर ऊपरी सीमा ही लगती है: ₹3 करोड़ से ऊपर turnover पर जुर्माना सीधे ₹1,50,000, और उससे नीचे प्रतिशत चलता है। यह जुर्माना खाते ऑडिट कराकर तय तारीख़ तक रिपोर्ट देने में चूक पर है — टैक्स पर नहीं, इसीलिए तब भी लगता है जब देना कुछ बनता ही न हो।

जो एक चीज़ इसे घटाती है वह है **section 273B**, जो कहता है कि जुर्माना नहीं लगेगा अगर assessee साबित कर दे कि चूक के पीछे *वाजिब वजह* थी। यह असली प्रावधान है और औपचारिकता नहीं: चला है auditor की बीमारी या मृत्यु, खातों की सचमुच की ज़ब्ती, portal के बैठने का दर्ज सबूत। नहीं चला है कि सितम्बर व्यस्त था, कि accountant दूसरी file पर था, या कि extension की उम्मीद थी। देर होनी ही है तो वाजिब वजह अभी बनती है, लिखकर, तारीख़ों के साथ — बाद में नोटिस आने पर जोड़ी नहीं जाती।

> **आपको क्या करना है**
>
> बुधवार होने वाला नहीं है, तो सोमवार बहाना नहीं, record बनाने में लगाइए: auditor को sign की तारीख़ पूछता हुआ email, उनका जवाब, और देर की असली वजह का नोट। वजह सच्ची हो तो वह file ₹1,50,000 की है, और नोटिस आने के बाद लिखी जाए तो किसी काम की नहीं। और रिपोर्ट की देरी को return तक मत खींचिए: 31 अक्तूबर अपनी जगह क़ायम है।

TCC की सलाह

इस हफ़्ते ये तीन काम कर लीजिए

1. **सोमवार, बुधवार नहीं:** auditor से sign करने की तारीख़ पूछिए। वह **30 सितम्बर** के बाद पड़े तो अभी तय कीजिए — या दबाव बनाइए, या s.271B जानकर मानिए और s.273B का record आज ही लिखकर बनाना शुरू कीजिए।
2. ₹10 करोड़ की सीमा बचा लेगी, यह मानने से पहले प्राप्तियों और भुगतान — दोनों पर **5% नक़द की जाँच** कर लीजिए। भुगतान की तरफ़ ही अक्सर गड़बड़ होती है, और बाद में सवाल का जवाब वही हिसाब देता है।
3. 7 अक्तूबर से पहले इस साल का अपना **s.17(5) blocked credit** एक सूची में निकाल लीजिए। काउंसिल ढील दे तो पहले ही दिन पता होगा कि क़ीमत क्या है; और किसी supplier की चूक ने credit खाया है तो वही file आपके व्यापार संगठन को अभी चाहिए।

GST डेस्क · काउंसिल

7 अक्तूबर के दो प्रस्ताव बदलेंगे कि कौन-सा credit बचेगा और कौन-सा मिलेगा

57वीं GST काउंसिल · 7 अक्तूबर 2026 · GST 2.0 के तहत प्रक्रिया सुधार

काउंसिल तरीक़ों पर बैठ रही है, दरों पर नहीं — वित्त मंत्री ने यही कहा है और दरों का कोई प्रस्ताव नहीं आना। उस सूची के दो मुद्दे आम ख़रीदार के लिए दरों के कई बदलावों से ज़्यादा मायने रखते हैं। पहला है **ITC की ढाल**: ईमानदार ख़रीदार को उस supplier के नतीजों से बचाना जो टैक्स वसूलकर जमा नहीं करता। उद्योग यह बात बरसों से उठा रहा है और इससे ख़ूब मुक़दमे हुए हैं, क्योंकि आज credit उससे छीना जाता है जिसने भरा, न कि उससे वसूला जाता है जिसने रखा।

दूसरा क़ानून में छोटा है और असर में बड़ा: s.17(5) के तहत **blocked credit** की पाबंदियाँ ढीली करना, जिन चीज़ों पर आज credit मिलता ही नहीं — मोटर गाड़ियाँ और कुछ सवारियाँ, खाना-पीना, outdoor catering, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएँ, club की सदस्यता और कुछ यात्रा सुविधाएँ। इनमें से हर एक असली P&L पर असली ख़र्च है, जिस पर आज ऐसा GST बैठा है जो वापस नहीं मिलता। दोनों तब तक प्रस्ताव हैं जब तक काउंसिल बैठ न जाए, और यह काउंसिल इस चक्र में एक बार टल चुकी है।

> **आपको क्या करना है**
>
> किसी प्रस्ताव के भरोसे कुछ भी दोबारा मत गढ़िए। उसकी जगह दो छोटे काम कीजिए। इस साल की अपनी s.17(5) की नामंज़ूरियाँ एक सूची में निकाल लीजिए, ताकि ढील आए तो पहले ही दिन पता हो कि आपके लिए इसकी क़ीमत क्या है, मार्च में पता न चले। और जहाँ किसी supplier की चूक आपका credit पहले ही खा चुकी है, वह file अक्तूबर के पहले हफ़्ते से पहले अपने व्यापार संगठन के प्रतिनिधि तक पहुँचाइए — काउंसिल के मुद्दे को आँकड़ों वाला जीता-जागता उदाहरण हिलाता है, आम शिकायत नहीं।

क्रेडिट डेस्क · RBI बुलेटिन

इस साल हर कसी हुई credit line के पीछे जो सवाल था, RBI ने उसका जवाब दिया है

RBI बुलेटिन, सितम्बर 2026 · credit-deposit का फ़र्क़ · निजी कॉरपोरेट निवेश

FY23 से बैंक credit जमा से तेज़ बढ़ा है, जिससे **credit-deposit ratio 80% के ऊपर** चला गया और वह सवाल उठा जो आपका banker शायद आपसे दोहरा चुका है: उधार देना टिक पाएगा या नहीं। सितम्बर के बुलेटिन का जवाब है कि ऊँचा CD ratio *अकेले* funding की कमज़ोरी नहीं दिखाता। तर्क यह है कि आज की मौद्रिक व्यवस्था में जमा तब बनती है जब बैंक उधार देते हैं, इसलिए credit देने से पहले देनदारियाँ जुटाना ज़रूरी नहीं; मार्च 2026 के आख़िर का ऊँचा ratio देनदारी की तरफ़ के फेरबदल से आया — सस्ता क़र्ज़, ज़्यादा पूँजी — और reserves को दोबारा लगाने से।

उसी बुलेटिन में तस्वीर का दूसरा आधा है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की मंज़ूर की गई **परियोजनाओं की संख्या और कुल लागत** 2025-26 में पिछले साल से बढ़ी, और अनुमानित पूँजी निवेश का बड़ा हिस्सा बुनियादी ढाँचे को मिला, जिसमें **बिजली** सबसे आगे। दोनों साथ पढ़िए: बैंकिंग व्यवस्था कह रही है कि उस पर बंदिश नहीं है, और उसने जो पैसा मंज़ूर किया है वह लंबी अवधि के बुनियादी ढाँचे में जा रहा है, बाक़ी economy के working capital में नहीं। इस साल आपकी limit महँगी हुई है या घटी है, तो व्यवस्था में जगह ख़त्म होने से बेहतर वजह यही है।

> **आपको क्या करना है**
>
> renewal आए तो "liquidity tight है" को वजह मत मानिए, क्योंकि ख़ुद regulator का बुलेटिन कह रहा है कि व्यवस्था में कमी नहीं है। बजाय इसके पूछिए कि आपकी file में क्या बदला — rating, turnover cover, security — क्योंकि जवाब अब वहीं बैठा है, और यही बातचीत आप जीत सकते हैं। ईमानदार जवाब यह हो कि बैंक का मन project lending की तरफ़ चला गया है, तो इसका मतलब है दाम पर बहस नहीं, panel बढ़ाइए।

ट्रेड डेस्क · BTA

“लगभग तय” का मतलब दस्तख़त नहीं, और दोनों के बीच की जगह में आपका दाम बैठा है

भारत–अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता · वाणिज्य मंत्री, 25 सितम्बर 2026

वाणिज्य मंत्री ने **25 सितम्बर** को समझौते को लगभग “तय” बताया, 22 सितम्बर को वॉशिंगटन में एक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करने के कुछ ही दिन बाद। जो शर्त वे दोहराते रहे हैं वह नहीं बदली: भारत तभी अंतिम रूप देगा जब शर्तें भारतीय माल को प्रतिस्पर्धियों के मुक़ाबले बेहतर दर दें — और उन्होंने प्रतिस्पर्धी गिनाए भी: वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया। उनके बराबर की दर सिर्फ़ नुक़सान हटाती है; उनसे बेहतर दर फ़ायदा है, और अड़ाई इसी पर है।

निर्यातक के लिए उस वाक्य का काम का मतलब है एक तारीख़ जो किसी ने दी नहीं। फ़रवरी में पहले चरण का ढाँचा घोषित हुआ था और फिर अमेरिकी टैरिफ का नक़्शा बदलने पर दोबारा खुल गया, यानी “लगभग तय” पहले भी कई महीने का मतलब रख चुका है। भाव उसी हिसाब से दीजिए। जो दस्तख़त हुआ ही नहीं उसे मान लेने की क़ीमत है ऐसा contract, जिसका दाम उस शुल्क दर पर बना है जो उस पर लगती ही नहीं।

> **आपको क्या करना है**
>
> वह tariff-change clause बनाए रखिए जो यह अख़बार जोड़ने को कह चुका है, और उसे समझौते पर नहीं, दर पर टिकाइए: लिखिए कि दाम किस शुल्क को मानकर बना है और बदलाव कौन उठाएगा, ताकि clause तब भी काम करे जब बदलाव समझौते से आए और तब भी जब दर बढ़ने से। कोई ख़रीदार अभी इस पर अड़े, तो यह काम की जानकारी है कि जोखिम उठाने का इरादा किसका है।

मार्केट डेस्क · लिस्टिंग

ख़ुद exchange बाज़ार में उतरा, और सपाट शुरुआत subscription से ज़्यादा कहती है

NSE IPO · ₹22,562 करोड़ · 24 सितम्बर 2026 को +0.84% पर लिस्ट

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज **24 सितम्बर** को लिस्ट हुआ। **₹22,562 करोड़** के साथ यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा issue है, सिर्फ़ 2024 के Hyundai Motor India के ₹27,870 करोड़ से पीछे, और पूरा का पूरा **offer for sale** था — मौजूदा हिस्सेदारों के 12.64 करोड़ शेयर, exchange ने नई पूँजी नहीं जुटाई। यह **5.71 गुना** भरा, जिसमें qualified institutional buyers **12.68 गुना** और non-institutional हिस्सा 6.55 गुना। anchor निवेशकों ने लगभग ₹6,746 करोड़ लिए।

फिर यह ₹1,785 के issue दाम से **0.84%** ऊपर खुला। जो book क़रीब छह गुना भरी हो और संस्थाएँ तेरह गुना तक गई हों, उसका सपाट खुलना यही बताता है कि दाम ने माँग पहले ही सोख ली थी — जोश बोली में चला गया और tape के लिए कुछ बचा नहीं। और यह उस हफ़्ते हुआ जब निफ्टी **लगातार सातवीं बार** गिरा। कारोबारी के लिए पढ़ने की बात इस शेयर की नहीं है: बात यह है कि सूचकांक के फिसलते रहने पर भी सही चीज़ के लिए संस्थागत पैसा अब भी बड़े आकार में आ रहा है — यह बाज़ार का छँटाई करना है, बाज़ार का जाना नहीं।

> **आपको क्या करना है**
>
> आप पैसा जुटाने की सोच रहे हैं — round, बैंक limit, या हिस्सा बेचना — तो काम का संकेत यह है कि गिरते बाज़ार में भी संस्थाएँ गुणवत्ता का दाम दे रही हैं, और दाम पर दे रही हैं, उससे ऊपर नहीं। ऐसे ख़रीदार के लिए तैयार रहिए जो मौजूद है, दिलचस्पी रखता है, और ज़्यादा देने को तैयार नहीं: साफ़ खाते, GST और income tax की मिलान की हुई स्थिति, और related-party की सूची में कोई चौंकाने वाली बात नहीं। और कैलेंडर के संयोग से यही चीज़ इस हफ़्ते का ऑडिट भी तैयार करता है।

बाज़ार

25 सितम्बर तक का हफ़्ता

सूचकांक	बंद भाव	हफ़्ता
Nifty 50	23,140.50	-0.9%
Sensex	73,895.74	-0.5%

लगातार सातवाँ घाटे वाला हफ़्ता, और अब सिलसिला ही ख़बर है। निफ्टी **205.90 अंक** (0.9%) गिरकर 23,140.50 और सेंसेक्स **399.22 अंक** (0.5%) गिरकर 73,895.74, और वजह बताई गई अमेरिकी Treasury yields का कई साल का ऊँचा स्तर तथा मज़बूत तेल। नीचे वही दो-तरफ़ा बाज़ार जो पिछले छह हफ़्तों से है, और बड़े पैमाने पर: विदेशी संस्थाओं ने हफ़्ते भर में शुद्ध **₹11,490.03 करोड़** बेचे जबकि घरेलू संस्थाओं ने शुद्ध **₹16,398.15 करोड़** ख़रीदे — और **पाँचों दिन** ख़रीदे। 25 सितम्बर तक के सितम्बर का फ़र्क़ और साफ़ है: FII ने **₹18,531 करोड़** निकाले, DII ने लगभग **₹52,617 करोड़** डाले। घरेलू पैसा बिकवाली सोख भर नहीं रहा, उस पर लगभग तीन गुना भारी पड़ रहा है — इसीलिए सात घाटे के हफ़्तों ने सूचकांक से 5% से भी कम लिया है।

राजस्थान डेस्क · ज़मीन

RIICO की बोली सोमवार को खुलती है, और जमा की खिड़की बंद हो चुकी है

RIICO ई-नीलामी · ऑनलाइन बोली 28–30 सितम्बर 2026 · EMD 25 सितम्बर को बंद

ऑनलाइन बोली **28 से 30 सितम्बर** तक चलेगी — जयपुर, भिवाड़ी, दौसा, कोटा, बीकानेर, राजसमंद और उदयपुर में: जयपुर का दौलतपुरा, भिवाड़ी का रबड़का, जयरामपुरा और दौसा–बांदीकुई Industrial and Logistics Hub, कोटा का कसार, बीकानेर का जोड़बीड़, राजसमंद का तनाजा का बासा, और उदयपुर के माल की तूस तथा पीपाड़। पूरे राज्य में सूची **584 प्लॉट** तक जाती है। 25 सितम्बर तक EMD जमा कर दी है तो सोमवार से बोली लगाइए; नहीं की, तो यह दौर आपके लिए बंद है और तैयारी अगले की कीजिए।

अगले दौर के लिए दो बातें साथ रखिए। आवंटन तेज़ी से बढ़े हैं — FY27 की पहली तिमाही में offer letter समेत **1,038** औद्योगिक प्लॉट, साल भर पहले के **214** के मुक़ाबले, यानी पाँच गुना; यह मौक़ा भी है और मुक़ाबला भी। और ज़मीन नीति अब **औद्योगिक reserve दरों में आगे की बढ़ोतरी रोक देती है**, प्लॉट के आकार के हिसाब से छूट के साथ, जो दो लाख वर्ग मीटर से ऊपर **40%** तक जाती है। जमी हुई reserve दर चुपचाप वाली बात है: एक साल रुकने का आम जुर्माना हट गया है, इसलिए बोली लगाने की वजह प्लॉट और जगह होनी चाहिए, अगले साल के दाम का डर नहीं।

> **आपको क्या करना है**
>
> इस हफ़्ते बोली लगा रहे हैं तो अपनी ऊपरी हद सोमवार से पहले तय करके लिख लीजिए — तीन दिन चलने वाली e-auction बनाई ही इसलिए जाती है कि वह बोली लगाने वाला मिल जाए जो अपनी हद खिसका दे। मंज़ूरी से पहले देख लीजिए कि ज़मीन की श्रेणी आपके इस्तेमाल से मेल खाती है, क्योंकि आवंटन के बाद use बदलवाना अलग आवेदन और अलग इंतज़ार है। इस दौर में नहीं हैं तो अगली deadline का नहीं, अगली सूचना का reminder लगाइए: बाँधने वाली तारीख़ हमेशा EMD होती है, और वह हमेशा उस बोली से पहले पड़ती है जिसकी ख़बर आपको मिलती है।

स्टार्टअप की खबरें

21 – 25 सितम्बर 2026

- **21 सौदों** में **$203.4 मिलियन** — भारत का दर्ज सबसे बड़ा सितम्बर वाला हफ़्ता, और पिछले हफ़्ते के $59–99 मिलियन से तीखा मोड़।
- दो चेकों ने इसे उठाया: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की **Ultraviolette** ने Yali Capital और TDK Ventures की अगुवाई में **$85 मिलियन** लिए, और enterprise-AI कंपनी **Ema** ने Creaegis की अगुवाई में **$77 मिलियन** का Series B जुटाया।
- **सबसे ज़्यादा पैसा AI को** — पाँच startup ने मिलकर $89.3 मिलियन लिए — और seed दौर भी चलता रहा, पाँच सौदों में $20.3 मिलियन। बेंगलुरु आठ सौदों के साथ आगे, दिल्ली-NCR छह के साथ पीछे।

रेफ़रेंस · तारीख़ें

महीना बदलने से पहले एक deadline, एक नीलामी और एक आँकड़ा

30 नवंबर 2026 तक की तारीख़ें · रविवार 27 सितम्बर से गिनी गईं

28–30 सितम्बर — RIICO की ऑनलाइन बोली। **28 सितम्बर** — अगस्त का IIP, जो बताएगा कि जुलाई वाली manufacturing की मज़बूती टिकी या नहीं। **30 सितम्बर** — AY 2026-27 की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, और वही तारीख़ जिस तक RBI के draft BC ढाँचे में business correspondent को बदलना है। **7 अक्तूबर** — 57वीं GST काउंसिल और MPC का ऐलान, एक ही बुधवार। **11 अक्तूबर** — सितम्बर की GSTR-1।

फिर **15 अक्तूबर** — Q2 की TCS return, Form 27EQ। **18 अक्तूबर** — Q2 का CMP-08, composition वालों के लिए। **20 अक्तूबर** — सितम्बर की GSTR-3B, मासिक भरने वालों के लिए। **31 अक्तूबर** — ऑडिट वालों की ITR और छमाही MSME-1। **15 नवंबर** — Q2 के TDS सर्टिफिकेट, Form 16A। **30 नवंबर** — s.92E के transfer pricing वालों की ITR। ऑडिट रिपोर्ट और जिस return को वह सहारा देती है, दोनों अब महीने भर की दूरी पर हैं और बीच में ऐसा कुछ नहीं जो किसी को हिलाए।

आपको क्या करना है

इस पखवाड़े में सिर्फ़ एक तारीख़ अपना जुर्माना साथ लाती है, और वह बुधवार है। बाक़ी दो मौक़े हैं, अपनी-अपनी घड़ी के साथ: नीलामी जब ख़त्म होगी तब ख़त्म होगी, और IIP वह जानकारी है जिस पर आप बाक़ी तिमाही काम कर सकते हैं। 7 अक्तूबर के बाद सब return है, और सूची की हर return सितम्बर की — एक ही काम, एक बार किया हुआ, उसी क्रम में जिस क्रम में तारीख़ें आती हैं।

इस हफ़्ते का सवाल

हर अंक में एक

"मेरा turnover ₹1.2 करोड़ है और लगभग सब बैंक से आता है। क्या मुझे बुधवार तक टैक्स ऑडिट कराना है?"

शायद नहीं — मगर जवाब उस जाँच पर टिका है जो मान लेने के बजाय करनी चाहिए। section 44AB की ₹1 करोड़ की सीमा **₹10 करोड़** हो जाती है, बशर्ते नक़द प्राप्तियाँ कुल प्राप्तियों के **5%** से ज़्यादा न हों *और* नक़द भुगतान कुल भुगतान के 5% से ज़्यादा न हों। दोनों शर्तें साथ चाहिए, और लोग भुगतान वाली शर्त पर चूकते हैं: पैसा बैंक से आता है क्योंकि ग्राहक ऐसे ही देते हैं, और फिर मज़दूरी, भाड़ा या supplier का advance नक़द जाता है और चुपचाप 5% पार हो जाता है। तो FY 2025-26 की कुल प्राप्तियाँ और कुल भुगतान लीजिए, दोनों तरफ़ नक़द का अनुपात अलग-अलग निकालिए, और हिसाब सँभालकर रखिए — पूछे जाने पर जवाब वही काग़ज़ देगा। दो रास्ते turnover से बेपरवाह आपको ऑडिट में खींच सकते हैं: presumptive scheme में हैं और presumptive दर से *कम* मुनाफ़ा दिखा रहे हैं जबकि आय छूट की सीमा से ऊपर है, या पिछले पाँच साल में 44AD से बाहर निकले हैं। और जाँच आपको ऑडिट में डाल दे, तो आपके पास तीन दिन हैं, कोई रियायत नहीं।

अपना सवाल भेजिए — हर अंक में एक का जवाब देते हैं

इकॉनमी एक नज़र में

रेपो रेट	5.25%	MPC 7 अक्टूबर
CPI (अगस्त)	4.82%	लगातार 10वाँ महीना
WPI (अगस्त)	9.92%	खुदरा से लगभग दोगुना
IIP (जुलाई)	6.7%	अगस्त का 28 सितम्बर को
credit-deposit अनुपात		>80%
FII (25 सितम्बर तक)		-₹18,531 cr
टैक्स ऑडिट	30 Sep	कोई extension अधिसूचित नहीं
ITR (ऑडिट वाले)	31 Oct	रिपोर्ट देर से जाए तब भी वही
GST काउंसिल		7 Oct

इनमें दो प्रस्ताव हैं और एक क़ानून। क़ानून वाला बुधवार है।

इनमें से कोई खबर आप पर लागू होती है ?

बस एक मैसेज कीजिए। हम बता देंगे कि आप पर क्या लागू होता है, कब तक करना है, और किस बात की चिंता नहीं करनी। फिक्स्ड मंथली फीस, कोई लॉक-इन नहीं, नोटिस आया तो वो भी हम देखेंगे — जैसे 1,100+ MSME के साथ पहले से कर रहे हैं।

लोग हमारे पास क्यों आते हैं

- फिक्स्ड मंथली फीस — न छुपा चार्ज, न लॉक-इन
- सब कुछ WhatsApp पर। नोटिस आया तो वो भी हम देखेंगे।
- 7 दिन में books बंद, हर महीने P&L डैशबोर्ड

किसी कारोबारी के काम की है? आगे भेज दीजिए।

The Consulting Crew

theconsultingcrew.in
hello@theconsultingcrew.in
WhatsApp +919251022710
जयपुर · पूरे भारत में

हम क्या करते हैं

GST · इनकम टैक्स · TDS · ROC · पेरोल · CFO सलाह · कंपनी और LLP रजिस्ट्रेशन

अगला अंक

रविवार, 4 अक्टूबर 2026

पिछले अंक

हर अंक, मुफ़्त

THECONSULTINGCREW.IN

खबरें कहाँ से

ऑडिट की तारीख़ क़ायम — extension नहीं आया — Whalesbook — CBDT holds 30 September, no extension granted, CAclubindia — why a request is not an extension, TaxGuru — the case for deciding early, LatestLY — what to do before the AY 2026-27 date · फ़ैसले के पीछे के आँकड़े — ANI — net direct tax ₹12.12 lakh crore, advance tax +16.18%, A2Z Taxcorp — corporate and non-corporate split · 7 अक्तूबर की काउंसिल — ITC की ढाल और blocked credit — IBTimes — process reforms, ITC and invoice rules, Business Standard — FM says process reforms, Business Today — invoice matching, ITC, MDR in focus, TaxO — 26 September summary · RBI बुलेटिन — credit-deposit अनुपात — IANS — a high CD ratio is not itself a vulnerability, IBTimes India, BestCurrentAffairs — the Bulletin's three articles, Business Standard — the H2 growth outlook · NSE की लिस्टिंग — Bloomberg — shares rise in debut after a $2.4 billion IPO, India TV — listing at a 0.84% premium, Upstox — what to know before the debut, HDFC Sky — listing date and issue detail · बाज़ार — 25 सितम्बर तक का हफ़्ता, और निवेश का बहाव — Upstox — a seventh consecutive weekly fall, Sunday Guardian — the closes and levels to watch, Liquide — weekly review and institutional flows · भारत–अमेरिका समझौता — Business Today — “done and dusted”, 25 September, India TV — only after preferential terms, Deccan Herald — the 22 September delegation · RIICO — 28–30 सितम्बर की बोली — Udaipur Times — EMD by 25 September, bidding 28–30, eAuctions India — 584 plots listed across Rajasthan, Business Standard — a fivefold jump in allotments, RIICO · स्टार्टअप फंडिंग — हफ़्ते का रिकॉर्ड — Inc42 — $203 Mn this week, Entrackr — funding and acquisitions, 21–26 September, Best Startup India — 21 deals, the biggest September week · दाम, पिछले अंक से आगे — Business Standard — August WPI at 9.92%, CNBC — August CPI at 4.82% · जुर्माने के प्रावधान — Bajaj Finserv — s.44AB limits and s.271B, CAclubindia — the extension question for AY 2026-27 · Ship-to GSTIN — अब भी रुका — Tax Update India — Advisory 668, GSTN — FAQs on the Ship-to field (PDF)

ज़रूरी सूचना। यह अख़बार The Consulting Crew अपने क्लाइंट और जान-पहचान वालों की जानकारी के लिए निकालता है। यह कोई कानूनी, टैक्स या निवेश की सलाह नहीं है, और इसे पढ़ने से हमारा-आपका क्लाइंट रिश्ता नहीं बनता। आँकड़े, दरें और तारीख़ें छपने के दिन तक की हैं और सरकार के नोटिफिकेशन से बदल सकती हैं। कुछ भी करने से पहले अपने केस के हिसाब से हमसे एक बार पूछ लीजिए। बाज़ार के आँकड़े सिर्फ़ जानकारी के लिए हैं, कोई शेयर खरीदने या बेचने की सलाह नहीं।